

सम्पादकीय

राजनीति का विस्तार और विस्तार की राजनीति के बीच सत्ता-विपक्ष की बैठकों के मायने

तो क्या 18 जुलाई की शाम को 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर समने आ जाएगी? देश को पता चल जाएगा कि एनडीए के साथ कौन-कौन हैं और विपक्ष के खेमे में कौन-कौन हैं? बंगलूरु में विपक्ष की बैठक 17-18 जुलाई को होनी है और भाजपा ने भी बहुत साल बाद एनडीए की बैठक 18 जुलाई को बुलाई है। कहा जा रहा है कि भाजपा को एनडीए की याद इसलिए आ रही है, क्योंकि विपक्ष एक होने की संभावना पर काम कर रहा है। उधर विपक्ष की मजबूरी है कि एक नहीं हुए, तो एक-एक करके खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर यह राजनीति का विस्तार है और विस्तार की राजनीति है। पहले बात विपक्ष की पटना के बाद यह विपक्ष की दूसरी काशिया होगी। क्या बंगलूरु में विपक्ष के गठबंधन को कोई नाम मिलेगा और वह अपना संयोजक चुनने में सफल रहेगा? विपक्ष को नारा और नीति पर भी काम करना होगा। आखिर मोदी ब्रांड के खिलाफ यह नारा नहीं चल सकता कि 'मोदी हटाओ, देश बचाओ' या 'मोदी को हराना है, सत्ता से हटाना है'। गठबंधन को नारा इस विमर्श के आसपास बुनना होगा कि विपक्ष सत्ता में आया तो क्या करेगा। रोजगार, महगाई जैसे मुद्दों का इलाज किस रूप में करेगा? उसे एक गेम चेंजिंग आइडिया की जरूरत तो होगी। क्या यह संघवाद हो सकता है, यानी अगर गठबंधन सत्ता में आया, तो राज्यों को अधिक अधिकार देगा। यह आइडिया कांग्रेस को नापसंद करने वाले ओडिशा के नवीन पटनायक, अंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड़ी और तेलंगाना के केसीआर को भा सकता है। एवं अन्य आइडिया न्याय योजना का है। राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि यूपीए सत्ता में आई, तो देश की सबसे गरीब बीस फीसदी जनता को छह हजार रुपये महीने यानी 72 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे। तब यह आइडिया किसी के गले नहीं उतरा। तो सरा आइडिया राइट दू हेल्प है। अभी मोदी सरकार आयुष्मान योजना चल रही है, जिसमें करीब दस करोड़ परिवर्गों को लाभ मिल रहा है। क्या विपक्ष 140 करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाकर अपनी राजनीति का विस्तार करने की संभावना तलाश सकता है? चौथा, सामाजिक सुरक्षा कानून है। सामाजिक सुरक्षा का तहत देश का हर जस्ता बोट बैंक में विस्तार कर राजनीति होगी। उधर एन बात करें, तो नौ साल बाकी कोई बैंक होगी। प्रधानमंत्री को किसी नए गेम आइडिया की जरूरत नहीं सिर्फ कुनवार का विस्तार की जरूरत है। इसके लिए शरू भी हो गया है। जीविराधियों का महागठबंधन वहां-वहां सियासी बुलडोज़ रहा है। महाराष्ट्र में शिवराज बाद एनसीपी इसकी कांग्रेसी आई है। कांग्रेस में रहे जाखड़ को भाजपा ने पंजाब मनमोहन सिंह सरकार रही एनटीआर की बेटी पुष्पदेवी को अंध्र प्रदेश की सीपी कर विस्तार की राजनीति का ट्रैलर दिखाया है। जीवी माझी भी एनडीए में आ अकाली दल से बात चल और प्रकाश राजभर से बीआईपी पार्टी के मुकेश से बात अंतिम दौर मायावती का मायावती साही रहा है। विपक्ष का रह एक ही आरोप होता है कि सीबीआई और इनकम कमिशनर का दुरुपयोग हो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी नियम संजय मिश्रा को आरोपित किया तो विपक्ष नहीं दिया, तो अमित शाह ने चेता दिया किसी एक के जाने से खुली की जरूरत नहीं है। ईडी शक्तियां मिली हुई हैं, वे जगह हैं। प्रधानमंत्री मोदी दलों के परिवारवाद और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की बात रहे हैं, लेकिन वह जनता साल का हिसाब देने के मामले भी लगे रहते हैं। भले वर्षों में मोदी सरकार राजनीति को अधिक मोर्चे पर ले रही है, उसका घोषणापत्र बढ़ावाल रहा है। अनुच्छेद 3 हटना, तीन तलाश खत्म होता है। इस तरकश के दो तीर हैं बड़ी बात है कि जनवरी मंदिर दर्शन के लिए खुले जाने समान नागरिक संघीयता प्रति तेजी से चल रहा है। वैष्णव ब्रह्मण्डन और अर्थात् संसार आदि को भी महंगे होते हैं, के महेनजर राजनीति के अंदर और विस्तार की राजनीति की हिस्सा मानना चाहिए।

अंतरिक्ष में परचम लहराने की तैयारी, 140 तक पहुंची टेक्नोलॉजी स्पेस स्टार्ट-अप्स की संख्या

वर्ष 2014 से पहले भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी स्पेस स्टार्ट-अप था, वहीं अब ऐसे स्टार्ट-अप की संख्या 140 तक पहुंच चुकी है। एक जमाने में भारत को सपरियों का देश कहा जाता था, लेकिन अब भारत अंतरिक्ष की दुनिया में 30 लाख करोड़ रुपये की है, जिससे भारत की हिस्सेदारी 57,431 करोड़ रुपये की है। लेकिन अगले पांच वर्ष में इसमें सालाना 48 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जिससे आगामी पांच वर्षों में भारत की स्पेस इक्नोलॉजी चाला छ 10 हजार करोड़ रुपये की हो जाएगी।



अग्रसर है। पिछेले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी भूमिका को पूरी तरह से बदल दिया है। वर्ष 2014 से पहले जहां भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी स्पेस स्टार्ट-अप था, वहां अब ऐसे पंजीकृत स्टार्ट-अप की संख्या 140 तक पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत में ऐसी कंपनियों की संख्या 400 से ज्यादा हो गई है। अभी अंतरिक्ष सेवाएं देने के मामले में भारत अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन के बाद पांचवें स्थान पर पहुंच चुका है। अभी पूरी दुनिया की स्पेस इकनॉमी लाभग्रह मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे सैटेलाइट और रॉकेट इंजन भी अपने देश में विकासित कर रहे हैं। इनमें से कुछ स्टार्ट-अप ने अगले एक दशक में 30 हजार सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। अब ज्यादातर भारतीय स्टार्ट-अप 'इनोवेशन' पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारतीय स्टार्ट-अप अपनी खुद की रिसर्च (अन्सर्थन) और अपने ही देश के काबिल इंजीनियरों के बल पर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे काबिल और सस्ते इंजीनियर हमारे इन्हीं स्टार्ट-अप में काम कर रहे हैं।

लौकर संग्रहालय पहुंचें पीएम मोदी, कहा- फ्रांस भारत की दोस्ती विश्व शांति में दे रही योगदान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में बैसिल दिवस परेड में बॉटौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैन्कों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मंत्री दो दिवसीय यात्रा पर यहां गुरुवार को पहुंचे थे। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों का संबोधित किया था पीएम मोदी फ्रांस के दो दिवसीय

का विषय है। ये भारतीय लोगों ने प्रति आपके स्नेह और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राजदूत पास्कल कानिन ने की पीएम की प्रशंसा वह पीएम मोदी के विजन पर अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए फ्रांस के राजदूत पास्कल कानिन ने कहा कि ठम्म मानना ?? है कि कुछ मिलाकर यह बेहद दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी है। इसलिए हम इससे बहुत खुश हैं मझे लगता है कि यह राष्ट्रपति मैत्र

यूरोप मंत्रालय के संस्टेनेबल सिटीज टास्क फोर्स के प्रमुख गेरार्ड तुलपन ने कहा कि ठस्टेनेबल सिटीज आज के प्रमुख विषयों में से एक है। मुझे लगता है कि उन्हें (पीएम मोदी) सही बात पता चली है।ठ..स्पष्ट रूप से प्रमुख समस्याओं में से एक भारत में आने वाली सभी शहरी आवार्द्धन के लिए समाधान ढूँढ़ना है। और यामीण से शहरी प्रवास के संदर्भ में, हमें और अधिक भागीदार बनाना

का आग्रह किया। इंडो-पैसिफिक कॉपरेशन रोडमैप पर कर रहे काम पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ साझा प्रेस वार्ता में कहा कि हमारे सहयोग को एक रचनात्मक रूप देने के लिए हम इंडो-पैसिफिक कॉपरेशन रोडमैप पर काम कर रहे हैं। इंडो-पैसिफिक दृग्युल्हर डिवेलपमेंट कॉपरेशन फंड के प्रस्ताव पर भी दोनों पक्ष चर्चा में हैं। इससे पूरे क्षेत्र में स्टार्टअप और इनावेशन को बढ़ावा

नींव के आधार पर अगले 25 वर्षों का रोडमैप बना रहे हैं। इसके लिए साहसिक एवं महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। भारत के लोगों ने स्वयं को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस यात्रा में हम फ्रांस को एक स्वाभाविक भागीदार के रूप में देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंको ने साझा प्रेस कार्मकार्स में कहा कि मुझे यहां आज बैस्टिल डे परेड में पंजाब रेजिमेंट



मणिपुरः ठीक नहीं है सेना पर कीचड़ उछालना, देश के लिए खतरनाक हैं ऐसे बयान

मणिपुर में सेना पर कोचड़ उठालने वाले भयानक देशद्वेष ह कर रहे हैं। यह वह सेना है, जिसकी बौद्धतृत असम, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर भारत का अभिष्ठ अंग बने हुए हैं। मणिपुर की भौगोलिक एकता परे भारत से जुड़ी हुई है। इसकी हिफाजत विभाजक मुद्द उठाकर नहीं की जा सकती। दो महीने से ज्यादा

कामना है कि चर्चों को जलाए जाने हत्याओं और हिंसा की एक भी फोटो या वीडियो विलेप अब देखने को मिलें। अगर शांति स्थापित करने वाले एक ही रास्ता है, तो क्या हमउस चुनेंगे? साधारणक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। लैकिन इसकी भवित्व पृष्ठभूमि है। 18 जून को मणिषुपुरे

नस्तु के आधार पर खड़ किए गए आख्यान की यह अनिवार्य त्रासर्दी होती हमणिरु में लगी आग ने पहली बार भारतीय सेना को परोक्ष रूप से किसी राजनेता का प्रतिवाद करने के बाध्य कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की 31 मई की रिपोर्ट : चौप आप डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौधरी ने कहा कि मणिपुर में झड़पों का संबंध

का छोड़ना पड़ा नासर के फलाव का यह परिणाम है कि भारत की भौगोलिक अखंडता की रक्षा में अंतिम अस्र सेना को निशाना बनाया जाने लगा। मणिपुर में सेना पर कीचींग उछालने वाल भयानक देशद्रोह कर रहे हैं। यह वह सेना है, जिसकी बढ़ाई लूट असम, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर

में बहुमत कुकर्यों का है, मगर इनमे करीब बीस फीसदी मैती हैं; इसके अलावा तमिल और अन्य जातीय लोग भी हैं। चक्रवर्ती बताते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के लाल चंद्रन का मारेह लाक घ्यामार और वहां से दक्षिण-पश्चिम चीन भेजा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर की तुलना में वहां कीमत चार-पांच गुना हो जाती



वक्त हो गया, मणिपुर में सूधरते-बिंगड़ते हालात के बीच आ रहे बयानों से हमारे माथे पर चिंता की लकीरें पड़नी चाहिए। अमेरिका में प्यार की पींगों के बाद अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सटी ने कोलकाता स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मणिपुर की घटनाएं मानवीय चिंता का विषय हैं। अंग्रेजी दैनिक द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, 'हम शांति की कामना करते हैं। जब आप हिंसा में बच्चों को मरता देख रहे हों, तब आपको परवाह करने के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं है। अगर कहा जाए, तो हम हर तरह से सहायता करने को तैयार हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत यह हो कि हर व्यक्ति जु़ड़ाव महसूस करे। हम वहां अधिक सहकार, अधिक परियोजनाएं और अधिक निवेश ला

मुख्यमंत्री एवं बीरेन सिंह ने जोरमध्यं
से अनुरोध किया कि मिजोरम के मैत्री
निवासियों की सुरक्षा के लिए कद
उठाए जाएं। रिपोर्टों के मुताबिक
मणिपुर में हिंसा के नतीजतन व
भागकर मिजोरम पहुंचे, बारह हजार
से ज्यादा ईसाई कुर्कियों की खोज
खबर नहीं ली। अगले दिन टाइम्स
ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार
बीरेन सिंह ने इंफाल में मीडिया
कहा, 'मुख्यतः कुकी दहशतगर्द हिंसा
बंद करें, वरना उन्हें नतीजे भुगत
पड़ेंगे। मैं हाथियारबद्ध मैत्रियों से अपील
करता हूँ कि वे कहीं भी हमले न करें
और शांति बनाए रखें।' शब्दाली
भावार्थ बहुत स्पष्ट है। अट्टीमेट
जैसी भाषा में इस कड़वे सरकी ज़िला
नहीं मिलती कि मौके के हिसाब
दोनों पक्ष मारकाट कर रहे हैं।
अलगाव की प्रबल भावना और धर्म

उग्रवाद विरोधी कार्रवाई से नहीं है। यह मुख्यतः जातीय हिंसा है। तीन दिन पहले बीरेन सिंह ने कहा था 'सुरक्षा बलों और उग्रवादियों में हुए मुठभेड़ में 40 कुकी मारे गए।' पहले बार यह भी हुआ कि सेना के अंदर मैती-कुकी को देखा जाने लगा विविधतापूर्ण देश की सेना इस स्थायी एवं अपरिवर्तनीय सिद्धांत की याद दिलाने को मजबूर हुई विभारतीय सेना के सभी ईकं नस्ल जाति, मत, लिंग-भेद से मुक्त हैं। सेना ने उस वीडियो को भी जारी कर दिया, जिसमें महिलाओं का एक मोर्चाबंद समूह चैनिकों का सशस्त्र उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से रोक रहा था। सेना महिलाओं पर गोली चला नहीं सकती थी, इसलिए उसे एक मैर्टिं उग्रवादी संगठन के 12 उग्रवादियों

भारत का अभिन्न अंग बने हुए हैं। मणिपुर पुलिस को मैती-कुकी आधार पर बांट दिया गया। अद्वैतीनिक बलों की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाए जाने लगे। सब कुछ बिखर जाए, तो पाकिस्तान और चौन के ही मंसूबे पूरे होंगे। मणिपुर में हिंसा के शुरुआती दौर में ही कथनक गढ़ा जाने लगा कि नशे के कारोबारी चोट पड़ने की वजह से हिंसा पर उत्तर आए हैं। इशारा कुकियों की ओर था। कुकु बहलुल पहाड़ी जिले चूरांगद्वारुप का सीमावर्ती इलाका मोरेह तरह-तरह के काले कारोबार का गढ़ है। सुदीप चक्रवर्ती ने अपनी चर्चित पुस्तक द ईस्टर्न गेट में मोरेह प्रवास का आंखें खोल देने वाला विवरण दिया है। होरोइन विक्रेता, एक मैती महिला ने उन्हें बताया कि लगभग 150 विक्रेताओं

है। इस धंधे में लगे कुछ असरदार तमिलों की पहुंच पूर्वोत्तर से लेकर हजारों मील दूर दृष्टिक्षण भारत तक है। जाहिर है, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इतने बड़े मकड़िजाल को विशाल भू-भाग में विभिन्न स्तरों पर सरकारी मिलीभगत के बिना सुरक्षित नहीं रख सकते। जहरीली मानसिकता सिर्फ एक बिंदु को देखती है। तकरीबन शांत चल रहे मणिपुर में तीन मई को भड़की हिंसा के बाद कुकी मैतियों के साथ नहीं रहना चाहते। उधर मणिपुर के नगाबहुल, करीब एक तिहाई हिस्से पर नगार्ड़ें की नेशनल सोशलिस्ट कार्डिसिल ऑफ नगार्ड़ें (आई-एम) पहले से ही दावा कर रही है। मणिपुर की भौगोलिक एकता पूरे भारत से जुड़ी हुई है। इसकी हिफाजत विभाजक मुद्दे उठाकर नहीं की सकती।

नोएडा जीएसटी नेटवर्क को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधान के दायरे में लाने का उत्तरप्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नोएडा इकाई ने कड़ा विरोध किया

(आधुनिक समाचार सेवा)

नोएडा। प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष नरेश कुचल के जारी एक बयान में कहा कि प्रतिनिधि मंडल नोएडा (ईडी) के हाथों छोटे और मध्यम व्यापारियों का अनावश्यक उत्तरदायक करने का प्रावधान लाया गया है। सरकार बार-बार कानूनों में बदलाव लाकर खाली टेंडर बढ़ावानों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों की थीर्थी की परेशानी ने लोकसभा द्वारा आयोजित व्यापारियों के लिए बड़ा खतरा हो गया। इससे छोटे व्यापारियों तक भारी कीमत चुकानी हो गयी है। नरेश कुचल ने कहा कि जीएसटी की पीएमएलए के दायरे में लाना छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा खतरा हो गया।



उत्पन्न हो जाएगी। फिर सड़क पर उत्तरने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को एक

उत्पन्न हो जाएगा।

प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष नरेश कुचल के बायान में कहा कि प्रतिनिधि मंडल नोएडा इकाई के व्यवसायी कुछ कठिनाइयों के कारण जीएसटी दाखिल करने में असमर्थ है, उन पर पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा मुक्कमा लाया जा सकता है। इस आदेश का उत्तरप्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल विरोध करता है। उन्होंने कहा कि इसके व्यापारी वर्ग में हावा व चिन्हाएँ हैं। इस आदेश से व्यापार जात में दबाव का माहौल है। इससे व्यापारी के उत्पीड़न की सभापता है और यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। एक तरफ तो सरकार व्यापार के दायरे में लाना छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा खतरा हो गया।

अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अनावश्यक और जरूरी और डरावने उनके समक्ष भुखमरी की समस्या

जीएसटीएन के पीएमएलए के तहत कानून व्यापारियों पर थोप रही है।

सतना कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने बदल दिया थाने का माहौल

(आधुनिक समाचार सेवा)

सतना। प्रभारी सुदीप सोनी ने कोलगवां में आने वाले दिवंग अव्ययी मन से बात करते हैं उन्होंने थाने का वह बदनाम है जहां एक अच्छा और सास्कृतिक और दबाव दी आई संभाल सकता है अपने कर्तव्यों का निवाह कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी कोलगवां में अपराधों पर नियंत्रण करने में हड्ड पल तैयार है।

कहना है कि अपराधी कोई भी हो जिसी भी तीव्रता के बजाय नहीं जाएगा उनकी बात को पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। सुदीप सोनी कोलगवां में अपराधों पर नियंत्रण करने में उन्हें उन्होंने खाली होते हैं उनका कहना है कि

सुदीप सोनी अपने अधीनस्थों को आंख और कान समझते हैं करते हैं इनका जब पूर्ण सहयोग मिलता है तभी हम किसी घटना का नियंत्रण करने में सफल होते हैं उनका कहना है कि

आवागमन के लिये सड़क न होने से निर्माण में आपसी सहमति न बनने काकों सम्बन्ध का सामान बाहर या था स्थानीय निवासियों को इस मामले में गंग के वर्तमान सरपथ

निर्माण में आपसी कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

कार्रवाई करते हैं जिसको सड़क पर देखा जाता है।

आवागमन के लिये सड़क न होने से

